शिक्षा | **सरकारी स्कूलों की पास प्रतिशतता 92 % के पार, मुख्यमंत्री सुक्खू बोले-यह विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत का परिणाम**

बारहवीं के नतीजों में टॉप-100 में आधे से ज्यादा मेधावी सरकारी स्कूलों के

शिमला। हिमाचल प्रदेश में बारहवीं कक्षा के नतीजों में टॉप 100 में आधे से ज्यादा मेधावी सरकारी स्कूलों से हैं। सरकारी स्कूलों की पास प्रतिशतता 92 प्रतिशत के पार रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मेहनती और प्रतिभाशाली हैं और उचित मार्गदर्शन, प्रोत्साहन मिलने पर वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हैं।

इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजों में 50 से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मेरिट सूची के टॉप 100 में शामिल हुए हैं। इस वर्ष टॉप 100 में 48 छात्राओं और 10 छात्रों ने स्थान बनाया, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 41 छात्राओं और 9 छात्रों की थी।

वर्ष 2024 में 23 छात्राएं और 7 छात्र और वर्ष 2023 में 33 छात्र, 9 छात्राएं टॉप-100 में स्थान बनाने में सफल रहे थे। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 92.02 रहा। जबकि वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 88.64, वर्ष 2024 में 73.76 प्रतिशत और वर्ष 2023 में 79.40 प्रतिशत रहा था। कई वर्षों के बाद इस बार 12वीं का ओवरऑल टॉपर सरकारी स्कूल से आया है। सकारात्मक परिणामों पर मुख्यमंत्री ने कहा विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत रंग लाई। इससे साफ है कि अभिभावकों का सरकार के फैसलों पर विश्वास है। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अवगत करवाने के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट करवाई गई हैं, वहीं मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण का अवसर दिया गया है। उधर, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो

विद्यार्थियों से बोले सीएम, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं

शिमला। मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार सुबह अपने सरकारी आवास ओकओवर से सचिवालय के लिए पैदल आए। रास्ते में उन्होंने पोर्टमोर स्कूल की छात्राओं से सीबीएसई पाठ्यक्रम पर बातचीत की। भविष्य में छात्राओं ने क्या बनना है। इसको लेकर सवाल भी किए। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बात करते हुए कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं और राज्य का मुख्यमंत्री हूं। आप भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर अपना लक्ष्य प्राप्त करना। इस दौरान कुछ छात्राओं ने मुख्यमंत्री के पांव छूए तो सीएम ने उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि कन्याएं पैर नहीं छूतीं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छोटा शिमला चौक पर चल रहे निर्माणकार्य का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ मेयर सुरेंद्र चौहान और सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम भी मौजूद रहे। ब्यूरो

पोर्टमोर की छात्राओं से बात करते सीएम। संवाद

सरकारी स्कूलों में पास परसेंट 92 फीसदी पार

सीएम बोले– व्यवस्था परिवर्तन का असर, बोर्ड रिजल्ट में टॉप 100 में आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूलों के बच्चे

वरिष्ठ संवाददाता ▌ शिमला

प्रदेश के 12वीं के बोर्ड रिजल्ट में इस बार सरकारी स्कूलों ने बाजी मारी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने छात्रों व शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस बार सरकारी स्कूलों का बोर्ड रिजल्ट 92 फीसदी पार रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में किए जा रहे व्यवस्था परिवर्तन के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजों में 50 से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मेरिट सूची के टॉप 100 में शामिल हुए हैं। यानी आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूलों से हैं।

इस वर्ष टॉप 100 में 48 छात्राओं और 10 छात्रों ने स्थान बनाया, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 41 छात्राओं और 9 छात्रों की थी। वर्ष 2024 में 23 छात्राएं और 7 छात्र तथा वर्ष 2023 में 33 छात्र और 9 छात्राएं टॉप 100 में स्थान बनाने में सफल रहे थे। सुधारों का प्रभाव पास प्रतिशतता में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 92.02 रहा। जबकि वर्ष 2025 में पास प्रतिशत

● कहा- ग्रामीण क्षेत्रों तक छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा

88.64, वर्ष 2024 में 73.76 प्रतिशत तथा वर्ष 2023 में 79.40 प्रतिशत रहा था। कई वर्षों के बाद इस बार 12वीं का ओवरऑल टॉपर सरकारी स्कूल से आया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के छात्र अंशित कुमार ने 99.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। अंशित की सफलता पर मुख्यमंत्री ने स्वयं उससे फोन पर बात कर बधाई दी। इन सकारात्मक परिणामों पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से ही व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इस सफलता के पीछे विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत और अभिभावकों का सरकार के फैसलों पर विश्वास है। सुधारों के चलते हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के मामले में 5वें स्थान पर पहुंचा है, जबकि पूर्व में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में 21वें स्थान पर पहुंच गया था। आज प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

स्कूल शिक्षा के लिए किया है 12वीं तक अलग निदेशालय का गठन

स्कूल शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक अलग निदेशालय और कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया है। शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अवगत करवाने के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट करवाई गई है, वहीं मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण का अवसर दिया गया है ताकि वे व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकें और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई है तथा क्लस्टर प्रणाली के माध्यम से संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

मेरिट में आधे स्थान सरकारी स्कूलों के

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला: शिक्षा विभाग में किए जा रहे 'व्यवस्था परिवर्तन' के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में किए गए प्रयासों का असर परीक्षा परिणामों में दिखाई दे रहा है। इस बार हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजों में 50 से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मेरिट सूची के टाप-100 में शामिल हुए हैं, यानी आधे से ज्यादा टापर सरकारी स्कूलों से हैं।

इस वर्ष टाप-100 में 48 छात्राओं और 10 छात्रों ने स्थान बनाया। वर्ष 2025 में यह संख्या 41 छात्राओं और 9 छात्रों की थी।

वर्ष 2024 में 23 छात्राएं और सात छात्र तथा वर्ष 2023 में 33 छात्र और 9 छात्राएं टाप-100 में स्थान बनाने में सफल रहे थे। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 92.02 रहा, जबकि वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 88.64, वर्ष 2024 में 73.76 प्रतिशत तथा वर्ष 2023 में 79.40 प्रतिशत रहा था।

कई वर्षों के बाद इस बार 12वीं का ओवरऑल टापर सरकारी स्कूल

शिक्षा क्षेत्र में सुधार से हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 92 प्रतिशत के पार

से आया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के छात्र अंशित कुमार ने 99.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि हिमाचल के सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। अंशित की सफलता पर मुख्यमंत्री ने स्वयं उससे फोन पर बात कर बधाई दी।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नई तकनीकों को अपनाते हुए विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में और सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है।

कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से ही व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य किया। इस सफलता के पीछे विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत और अभिभावकों का

सरकार के फैसलों पर विश्वास है। सुधारों के चलते हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पूर्व में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में 21वें स्थान पर था। प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। पिछले तीन वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 12वीं कक्षा तक अलग निदेशालय और कालेजों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया है।

-सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री।

पंजाब केसरी
THU,07 MAY 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 3

व्यवस्था परिवर्तन का असर, टॉप 100 में आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूलों से

शिमला, 6 मई (ब्यूरो): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा विभाग में किए जा रहे 'व्यवस्था परिवर्तन' के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मेहनती और प्रतिभाशाली हैं और उचित मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिलने पर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हैं।

यही कारण है कि इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजों में 50 से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मैरिट सूची के टॉप-100 में शामिल हुए हैं, यानी आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूलों से हैं।

इस वर्ष टॉप-100 में 48 छात्राओं और 10 छात्रों ने स्थान बनाया, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 41 छात्राओं और 9 छात्रों की थी। वर्ष 2024 में 23 छात्राएं और 7 छात्र तथा वर्ष 2023 में 33 छात्र और 9 छात्राएं टॉप-100 में स्थान बनाने में सफल रहे थे। बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि सुधारों का प्रभाव पास प्रतिशतता में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 92.02 रहा, जबकि वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 88.64, वर्ष 2024 में 73.76 प्रतिशत तथा वर्ष 2023 में 79.40 प्रतिशत रहा था। कई वर्षों के बाद इस बार 12वीं का ओवरऑल टॉपर सरकारी स्कूल से आया है।

उधर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसा नई तकनीकों को अपनाते हुए विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में और सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है।

व्यवस्था परिवर्तन से शिक्षा को पंख

जमा दो के रिजल्ट में टॉप-100 में आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूलों से, रंग लाए बेहतर प्रयास

दिव्य हिमाचल ब्यूरो – शिमला

शिक्षा विभाग में किए जा रहे 'व्यवस्था परिवर्तन' के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में किए गए प्रयासों का असर परीक्षा परिणामों में दिखाई दे रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मेहनती और प्रतिभाशाली हैं और उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने पर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजों में 50 से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मेरिट सूची के टॉप-100 में शामिल हुए हैं। यानी आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूलों से हैं। इस वर्ष टॉप-100 में 48 छात्राओं और 10 छात्रों ने स्थान बनाया, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 41 छात्राओं और 9 छात्रों की थी। वर्ष 2024 में 23 छात्राएं और सात छात्र तथा वर्ष 2023 में 33 छात्र और नौ छात्राएं टॉप-100 में स्थान बनाने में सफल रहे थे। सुधारों का प्रभाव पास प्रतिशतता में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 92.02 रहा, जबकि वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 88.64, वर्ष 2024 में 73.76 प्रतिशत तथा वर्ष 2023 में 79.40 प्रतिशत रहा था। कई वर्षों के बाद इस बार 12वीं का ओवरऑल टॉपर सरकारी स्कूल से आया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के छात्र अंशित कुमार ने 99.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। अंशित की सफलता पर मुख्यमंत्री ने स्वयं उससे फोन पर बात कर बधाई दी। इन सकारात्मक परिणामों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से ही व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य किया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इस सफलता के पीछे विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत और अभिभावकों का सरकार के फैसलों पर विश्वास है। सुधारों के चलते हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंचा है।

पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव

आज प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्कूल शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक अलग निदेशालय और कालेजों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया है।

- शिक्षा में सुधार से सरकारी स्कूलों की पास पर्सेंटेज भी 92 प्रतिशत के पार

व्यवस्था परिवर्तन का असर, टॉप 100 में आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूलों से

शिक्षा क्षेत्र में सुधार से सरकारी स्कूलों का पास परसेंट भी 92 प्रतिशत के पार

सवेरा ब्यूरो

शिमला, 6 मई : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में किए गए प्रयासों का असर परीक्षा परिणामों में दिखाई दे रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मेहनती और प्रतिभाशाली हैं और उचित मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिलने पर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हैं।

यही कारण है कि इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजों में 50 से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मेरिट सूची के टॉप-100 में शामिल हुए हैं यानी आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूलों से हैं। इस वर्ष टॉप-100 में 48 छात्राओं और 10 छात्रों ने स्थान बनाया, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 41 छात्राओं और 9 छात्रों की थी। वर्ष 2024 में 23 छात्राएं और 7 छात्र तथा वर्ष 2023 में 33 छात्र और 9 छात्राएं टॉप-100 में स्थान बनाने में सफल रहे थे।

सुधारों का प्रभाव पास प्रतिशतता में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 92.02 रहा। जबकि वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 88.64, वर्ष 2024 में 73.76 प्रतिशत तथा वर्ष 2023 में 79.40 प्रतिशत रहा था। कई वर्षों के बाद इस बार 12वीं का ओवरऑल टॉपर सरकारी स्कूल से आया है।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के छात्र अंशित कुमार ने 99.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। अंशित की सफलता पर मुख्यमंत्री ने स्वयं उससे फोन पर बात कर बधाई दी।

इन सकारात्मक परिणामों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से ही व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कार्य किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इस सफलता के पीछे विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत और अभिभावकों का सरकार के फैसलों पर विश्वास है।

वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्कूल शिक्षा के लिए 12वीं कक्षा तक अलग निदेशालय और कॉलेजों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया है। शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अवगत करवाने के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट करवाई गई हैं, वहीं मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण का अवसर दिया गया है, ताकि वे व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकें और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट यूनिफॉर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई है तथा क्लस्टर प्रणाली के माध्यम से संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नई तकनीकों को अपनाते हुए विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में और सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है।